



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 8 राँची, बुधवार 19 फाल्गुन, 1937 (श०)
9 मार्च, 2016 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 24-31 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4—झारखण्ड अधिनियम
भाग 1—क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उप-स्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1—ख—मैट्रिकुलेसन.आई.ए.,आई.एस.सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9- विज्ञापन ---
भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क—बन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	पूरक-- ... पूरक अ ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

8 फरवरी, 2016 ई०।

संख्या-वि०स०वि०-46/2015-165/वि०स०। झारखण्ड विधान सभा की अधिसूचना संख्या-46/2015-01, दिनांक 6 जनवरी, 2016 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा की चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र में दिनांक-21 दिसम्बर, 2015 को पारित प्रस्ताव के आलोक में "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2015" पर विचार के लिए झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-72 क अधीन गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 29 फरवरी, 2016 तक विस्तारित किया जाता है।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, रांची।

अधिसूचना

29 फरवरी, 2016 ई०।

संख्या-जनसम्पर्क-02/05-406/वि०स०। सभा-सचिवालय की अधिसूचना सं०-286 दिनांक, 26 फरवरी, 2016 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा ने झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा

कार्य संचालन के नियमों के दिये गये स्थायी आदेश क्रमांक-105 एवं 106 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में गठित वर्ष 2015- 16 की प्रेस सलाहकार समिति का कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 2016 तक विस्तारित किया जाता है ।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,
बिनय कुमार सिंह,
 प्रभारी सचिव,
 झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

अधिसूचना

22 फरवरी, 2016 ई०।

संख्या-आंत0-02/2015-423/वि०स०। झारखण्ड विधान-सभा के अधिसूचना सं०-आंत-02/15-36, वि०स०, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के क्रम में झारखण्ड विधान-सभा की आन्तरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति का कार्यकाल दिनांक-31 मार्च, 2016 तक विस्तारित किया जाता है।

मा०अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,
 प्रभारी सचिव
 झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

अधिसूचना

12 मार्च, 2015 ई०।

संख्या-कार्य०-18/2015-425/वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-233(1) के अधीन दिनांक-11 मार्च, 2015 को श्री ग्लेन जोसेफ ग्लाॅस्टन, स०वि०स० द्वारा झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची एवं क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा पलामू में पाँच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का समायोजन एवं सेवा नियमितीकरण विषय से

संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना पर सम्यक् विचार तथा समाधान हेतु आसन से दिये गये नियमन के आलोक में श्री दिनेश उराँव, माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

01.	श्री सरयू राय	संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य
02.	श्रीमती नीरा यादव	मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग	सदस्य
03.	श्री हेमन्त सोरेन	नेता प्रतिपक्ष	सदस्य
04.	अध्यक्ष	झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची	सदस्य
05.	प्रधान सचिव	वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य
06.	प्रधान सचिव	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	सदस्य
07.	प्रधान सचिव	मानव संसाधन विकास विभाग	सदस्य।

सभा सचिव इसके सचिव होंगे। समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिनों का होगा।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सुशील कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

अधिसूचना

22 फरवरी, 2016 ई०।

संख्या-वि०नि०अनु०स०-01/15-425/वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 223 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए गठित विधायक निधि अनुश्रवण समिति का कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 2016 तक के लिए विस्तारित की जाती है।

मा०अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

अधिसूचना

22 फरवरी, 2016

संख्या-प्रदूण-01/15.427/वि०स०। झारखण्ड विधान सभा के अधिसूचना सं०- प्रदूण-01/2015-48, दिनांक-23 फरवरी, 2015 द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-257 के अधीन वर्ष-2015-16 के लिए गठित विधान सभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का कार्यकाल दिनांक-31 मार्च, 2016 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,
बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची ।

अधिसूचना

22 फरवरी, 2016 ई०।

संख्या-पर्यटन विकास समिति-01/2015-431/वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की अधिसूचना सं०-60, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के क्रम में दिनांक-31 मार्च, 2016 तक के लिए पर्यटन विकास समिति को विस्तारित की गई है।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,
बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

अधिसूचना

22 फरवरी, 2016

सं०- सदा०स०-01/15-433/वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-40, दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए गठित झारखण्ड विधान सभा की सदाचार समिति का कार्यकाल दिनांक-31 मार्च, 2016 तक विस्तारित किया जाता है।

मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,
बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रांची।

अधिसूचना

22 फरवरी, 2016 ई०।

संख्या-जि०परि०एवं पं०रा०स०-01/15-443/वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-38, दिनांक-23 फरवरी, 2015 के क्रम में जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति का कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 2016 तक विस्तारित किया जाता है।

मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,
बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रांची।

अधिसूचना

22 फरवरी, 2016 ई०।

संख्या-झा०वि०स०(या०)-01/15-471/वि०स०। झारखण्ड विधान-सभा के अधिसूचना सं०-झा०वि०स० (या०)-01/15-86, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के क्रम में झारखण्ड विधान-सभा की याचिका समिति का कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 2016 तक विस्तारित किया जाता है।

मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,
बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रांची।

अधिसूचना

29 फरवरी, 2016 ई०।

संख्या-02स्था०-179/09-474/वि०स०। श्री नृपेन्द्र कुमार सिंह, अपर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची की आयु-60(साठ) वर्ष पूरी होने के फलस्वरूप झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-73 एवं उनके साथ वंचित वित्त विभाग के संकल्प सं०-07वि०स०प०-56/02का-5826, दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 के अनुसरण में इन्हें 29 फरवरी, 2016 के अप० से सेवानिवृत्त किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

नवीन कुमार,

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

अधिसूचना

22 फरवरी, 2016 ई०।

संख्या-प्राक्कलन-01/2015-475/वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा के अधिसूचना सं०-प्राक्कलन-78, दिनांक-23 फरवरी, 2015, 106, दिनांक 2 फरवरी, 2015, 138, दिनांक-16 मार्च, 2015 द्वारा झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली-239 के अधीन वर्ष 2015-16 के लिए गठित झारखण्ड विधान-सभा की प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 2016 तक विस्तारित की गयी है।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

अधिसूचना

22 फरवरी, 2016

संख्या- वि०स०(विशेष)-01/2015..479../वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-84, दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए गठित झारखण्ड विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 2016 तक विस्तारित किया जाता है।

मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

अधिसूचना

26 मई, 2016 ई०।

संख्या-ध्या०प्र० एवं अना०प्र०-04/2015-490/वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक-19 मार्च, 2015 को सदन में श्री शिवशंकर उराँव एवं अन्य स०वि०स० की गुमला जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधीन वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक में निर्मित सड़कें, पुल-पुलियों के निर्माण कार्य की जाँच कराकर निर्माण कार्य पूरा कराने एवं निर्माण में बरती गई कथित अनियमितताओं के लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई करने विषयक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन में हुए वाद-विवाद के आलोक में उपर्युक्त विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन के नियम-223(1) के अधीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा द्वारा गठित विशेष समिति का कार्यकाल एक माह अर्थात् दिनांक-26 जून, 2015 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सुशील कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

Department of Information Technology & e-Governance

Notification

4th December, 2015

JHARKHAND COMMUNICATION TOWERS AND RELATED STRUCTURES POLICY, 2015

No.- IT/ Tower Policy-30/2015 (Part)--Government of Jharkhand is determined to promote the projects related to ICT & IT based communication system. In order to strengthen this core Information and Communication infrastructure, the State intends to further facilitate effective transformation of the socio-economic scenario through accelerated equitable and inclusive economic growth by encouraging provision of quality infrastructure for connectivity & telecommunication services across the State, especially in the rural and remote areas of the State in a uniform and time bound manner.

Keeping in view the renewed requirements of the State along side the latest Information and Communication Technology (ICT) developments and the need to ensure that the access to and benefits of ICT percolate to urban & rural masses amid the changing economic environment, the State Government has decided to frame the **JHARKHAND COMMUNICATION TOWERS AND RELATED STRUCTURES POLICY, 2015**

1. Short title, extent and commencement:

- 1.1 This Policy may be called the Jharkhand Communication Towers and Related Structures Policy, 2015;
- 1.2 It shall extend to the whole of the State of Jharkhand excluding cantonment areas therein;
- 1.3 The Policy shall not be in violation or supersession of the provisions contained in the Indian Telegraph Act, 1885 and Indian Wireless Telegraphy Act 1933 in any way.
- 1.4 This policy shall take effect from the date of its Notification.

2. Definition:

In this Policy, unless otherwise required in the context:

- 2.1 "Applicants" means the Infrastructure Provider and/or Telecom Service Provider duly registered/licensed respectively by Deptt. of Telecommunication, Govt. of India, New Delhi
- 2.2 "Section" means a section of the Act;

- 2.3 All words and expression used in this Policy and not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act;
- 2.4 "Chief Executive Officer" (CEO) means:
- 2.4.1 In relation to a Municipal Corporation, the Municipal Commissioner, and
- 2.4.2 In relation to the Municipal Council or Nagar Panchayat, the Municipal Executive officer.
- 2.5 "Communication/Mobile Tower" means the telegraph apparatus including but not limited to: Tower/Poles along with multiple antennas for Ground Base Tower (GBT) /Roof Top Tower (RTT)/ Roof Top Pole (RTP), Pre-fabricated/masonry structure shelter/s for installation of BTS & other equipments. Duct, Fiber, cable, Guard Room etc. Any alternate power source viz Battery, Solar, DG etc. Any other additional equipments etc as may deemed to be necessary by the Infrastructure Provider/Telecom service Provider for effective operations.
- This will not include the antennas installed for domestic purpose, small pole/s for extending landline connections, tower installed in campus of institutions/office for LAN/WAN for their own use.***
- 2.6 "Municipality" means an institution of Local Self-Government constituted under section 3(2) of the Jharkhand Municipal Act 2011 read with Article 243Q of the Constitution of India, and includes a Municipal corporation, a Municipal Council and Nagar Panchayat referred to in section 3 (2) of Jharkhand Municipal Act, 2011;
- 2.7 "Telecom Service Provider (TSP)" means and includes a person, firm, association of persons or company who is duly licensed by Deptt. of Telecom, Govt. of India under section 4 of the Telegraph Act, 1885 for providing inter alia mobile phone services, internet and data transfer services etc.
- 2.8 "Infrastructure Provider(IP)" means and includes a person, firm, associations of persons or company who is duly licensed by Deptt. of Telecom, Govt. of India and duly authorized to install passive telecom infrastructure such as Communication/Mobile Tower, Dark Optical fibres and other equipments for effective operations of telecom services.
- 2.9 "State" means state of Jharkhand
- 2.10 "permission" means any permission pertaining to this Policy.
- 2.11 "Nodal Authority" means Pr Secretary/Secretary IT to whom applicants will apply for single window permission/clearance.

2.12 "Panchayat Samiti" means a Panchayat Samiti constituted under section 32 of Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001

2.13 "Block" means such local area in a district which the state govt may constitute to be a block.

2.14 "Panchayat Area" means territorial area of a panchayat constituted under Jharkhand Panchayat Raj Act 2001.

3. **Application for Registration:**

Any applicant, who intends to erect any communication tower, shall make an application to the nodal authority along with the following documents and requisite fee as prescribed:

- I. Copy of relevant license / Infrastructure Provider Registration Certificate from Department of Telecommunications, Govt. of India.
- II. Copy of SACFA clearance / copy of SACFA application for the said location submitted to WPC wing of DoT with registration number as WPC acknowledgement along with undertaking that in case of any objection/ rejection, TSPs/ IPs will take corrective actions/ remove the tower.
- III. Copy of structural stability certificate for ground based tower. In case of roof top BTS towers, structural stability certificate for the building and tower based on written approvals of any authorized Structural Engineer of state/local bodies/Central Building Research Institute (CBRI), Roorkee/ IIT/NIT or any other agency authorized by local body.
- IV. Copy of the type test certificate issued by Automotive Research Association of India (ARAI) to the manufacturers of the Diesel Generator (DG) Sets.
- V. Copy of clearance from Fire Safety Department only in case for high rise buildings where Fire Clearance is mandatory.
- VI. For forest protected areas, the copy of clearance from State Environment & Forest Department, if applicable.
- VII. No Objection Certificate (NOC) from Building Owner / entities having roof top rights or roof top tenants in case of roof based tower/ land owner in case of ground based tower, as the case may be.
- VIII. Acknowledgement receipt issued by TERM Cells (DoT) of the self-certificate submitted by Telecom Service Provider/ Infrastructure Provider in respect of mobile tower/ BTS (ground based/ roof top/ Pole/ wall mounted) in the format as prescribed by TEC, DoT, establishing / certifying that all General Public areas around the tower will be within safe EMR exposure limit as per peak traffic measurement after the antennae starts radiating.

- IX. In case the tower is in the vicinity or adjoining to high or low tension electric line, then its distance from the same shall be clearly indicated in the drawings. However TSP/IP will comply norms of minimum prescribed distance from HT/LT line.
- X. Indemnity Bond (Form III) to take care of any loss or injury due to accident caused by the tower (including a declaration to the effect that the applicant shall take special precaution for fire safety and lightening and he shall be solely responsible for paying all kinds of compensation and damages and would be responsible for any civil or criminal case arising therefore.
- XI. Copy of receipt of the fee deposited for Registration.

4. Fee structure :

A. For new Registration

4.1 Registration fee shall be deposited before filling request for permission/NOC to the nodal authority at following rates:

i. Registration Fee

- 1. In Municipal Corporation/Municipality area - 20,000/- per tower (Rs Twenty thousand per tower) to be deposited in Municipal Corporation/Municipality office.
- 2. In Nagar Panchayat Area/Nagar Parisad Area - 15,000/- per tower (Rs Fifteen thousand per tower) to be deposited in Nagar Panchayat Office/ Nagar Parisad Office.
- 3. In Panchayat Samiti Area- 10,000/- per tower (Rs Ten thousand per tower) to be deposited in Panchayat Samiti office at Block Level .

4.2 For all existing Mobile/Communication Tower TSP/IP has to deposit one time registration fee as per fee structure mentioned in para 4.1 above within 90 days of this notification along with list of Communication Towers.

5. Refund of fee to the applicants:

In case the application for permission is rejected, the fee paid under the para- 4 shall be returned to the applicant within one month from date of rejection, after deducting Rs 5000/- as administrative charge.

6. Places permissible for erecting Towers:

- a) All types of Residential/Multi Storey Building/Group Housing buildings
- b) All types of Industrial/Commercial Buildings
- c) All types of Institutional Building
- d) Open lands

e) In Govt. Bldg/Semi Govt. Bldg or premises after due permission from the authorized officer.

7. Authority to grant permission:

Authority will comprise of following officer which will act as single window for permission

- i) Pr. Secretary /Secretary, IT & e-Governance – Chairman
- ii) Pr. Secretary /Secretary, Forest, Environment & Climate Change or officer nominated by Pr. Sec./Sec., but not below the rank of Deputy Secretary – member
- iii) Pr. Secretary /Secretary, Home, Jail & Disaster Management Department or officer nominated by Pr. Sec./Sec., but not below the rank of Deputy Secretary – member
- iv) Pr. Secretary /Secretary, Urban Development & Housing or officer nominated by Pr. Sec./Sec., but not below the rank of Deputy Secretary – member
- v) Pr. Secretary /Secretary, Revenue, Registration & Land Reforms Deptt. or officer nominated by Pr. Sec./Sec., but not below the rank of Deputy Secretary – member
- vi) Pr. Secretary /Secretary, Rural Development (Panchayati Raj) or officer nominated by Pr. Sec./Sec., but not below the rank of Deputy Secretary – member
- vii) Pr. Secretary /Secretary, Rural Development (Rural Works) or officer nominated by Pr. Sec./Sec., deptt. but not below the rank of Deputy Secretary – member
- viii) Pr. Secretary /Secretary, Health, Medical Education & Family Welfare Deptt. or Specialist Doctor nominated by Pr. Sec./Sec./Officer not below the rank of Deputy Secretary – member
- ix) Member, State Pollution Control Board
- x) DDG, TERM/Director, TERM - member

Above committee will meet fortnightly to discuss the pending permission. Participation of members from Health, Medical Education & Family Welfare Deptt. & State Pollution Control Board will be mandatory. Out of total nine members or their representatives, four members or their representatives must be available to complete quorum.

8. Sharing of Sites:

The Telecom Service Provider/Infrastructure Provider may share the towers for fixing their respective antennas. However second/third/fourth TSP will apply with all the document mentioned in para 3. In case of shared site, all the shared TSPs will nominate one single contact points location wise with whom further communication can be done in future.

9. Procedure for permission:

On receipt of application along with requisite fee or say registration fee in Form-I, the authority shall take decision within 60 days from the date of application. The application must contain all the documents mentioned in para-3 along with registration fee. The receipt

of application will be issued by officer authorized by nodal authority. In case the documents submitted for permission are complete in all respects along with receipt of fee deposited and then decision is not conveyed within 60 days, deemed permission shall be assumed, provided that the same is in accordance with the prescribed rules.

10. Applicant to keep the norms prescribed for the level of air and noise pollution:

It shall be necessary for the applicant to keep the level of air and noise pollution within parameters prescribed by the Jharkhand State Pollution Control Board. A certificate issued by the generator set manufacturer for the noise and air pollution, shall be considered as no objection certificate.

11. Cell on Wheels :

Formal Permission /NOC is not required for the installation of COW (Cell on Wheels), provided that COW is being placed maximum for thirty days. Before installation of COW formal intimation will be required along with reason for installation of COW. If COW is being installed for more than 30 days then it will be treated as normal communication tower and formal permission will be required and IP/TSP has to take NOC after paying requisite fee mentioned in para 4.1.

12. No Coercive Action:

Telecom installations are lifeline installations and a critical infrastructure in mobile communication. In order to avoid disruption in mobile communication, an essential service, sealing of BTS towers / disconnection of electricity may not be resorted to without the consent of the respective TERM Cell of DoT in respect of the EMF related issues. ***However if it has been found that the tower/RTT/Pole/Antenna has been installed in contravention to the provisions mentioned in this policy then such towers/RTT/Pole/Antenna will be removed with advance notice of 90 day. Penalty in this case will be levied as per para 13.***

13. Penalty:

If an operator violates any provision of this Policy, it shall be liable to be penalized as per following term and condition-

- (i) As soon as Nodal officer comes to know that any provision has been violated, a show cause will be issued to TSP/IP. TSP/IP has to reply within 15 days from date of service of notice.
- (ii) If reply is not satisfactory then initial fine of Rs. 1,00,000/- (Rs One Lac) will be charged. The TSP/IP has to submit Compliance for such site as per policy within 30 days. Failing this TSP/IP will be penalized by Rs. 5000/- per day after 30 days period till compliance or removal of the tower/RTT/Pole/antenna.

14. Redressal of Public Grievances

In order to actively address Public Grievances relating to installation of towers and issues related to Telecom Infrastructure, State Govt. has constituted State-level Telecom committee (STC) & District Level Telecom committee (DTC) in all districts as prescribed below :-

I. District Level Telecom committee (DTC)

- 1 Deputy Commissioner
Chairman
- 2 Deputy Collector (Gen)
Convener
- 3 Superintendent of Police
Member
- 4 District Medical Officer
Member
- 5 Executive Engineer (Building Construction Deptt.)
Member
- 6 District Officer (State Pollution Control Board)
Member
- 7 Representative, TERM (Telecom Enforcement Resource & Monitoring)-Jharkhand
Member
- 8 District Head of BSNL
Member
- 9 District Head of Telecom/Infrastructure Provider Concerned
Member
(against whom complaints are received)
- 10 An eminent public person (to be nominated by chairman of DTC)
Member
- 11 Representative, Municipal Corporation/Municipality/
Nagar Panchayat/Nagar Parishad/ Panchayat Samiti Member

Duties & Functions

- (i) DTC shall deal with public grievances relating to installation of Mobile Towers and issues related to telecom infrastructure in the respective district.
- (ii) DTC shall convene meeting once in a month & resolve the public grievances in a timebound manner.
- (iii) The committee (DTC) may give the company (Telecom Service Provider) an opportunity to rectify the defects, if the committee feel so.

- (iv) The recommendations of DTC shall be adhered to by Municipal Corporation/Municipality/Nagar Panchayat/Nagar Parishad/ Panchayat Samiti or any other authority related to the subject.
- (v) The TSP can also approach DTC for redressing their grievances, if any.
- (vi) Telecom Service Provider or petitioner/complainant may file appeal before STC within 15 days from the date of receipt of the DTC's final decision, under intimation to the chairman of DTC.

II. State Telecom Committee (STC)

- 1 Secretary, Information Technology & e-Gov. Department
Chairman
- 2 Director, Information Technology & e-Gov. Department
Convener
- 3 Secretary, Building Construction Department
Member
- 4 Pr. Secy./Secy., Home, Jail & Disaster Management Department
Member
- 5 Pr. Secy./Secy., Health, Medical Education & Family Welfare Deptt.
Member
- 6 Pr. Secy./Secy., Urban Development & Housing Department
Member
- 7 Pr. Secy./Secy., Revenue, Registration & Land Reforms Department
Member
- 8 Pr. Secy./Secy., Forest, Environment & Climate Change Department
Member
- 9 Pr. Secy./Secy., Rural Development Deptt.
Member
- 10 Chairman, State Pollution Control Board
Member
- 11 Deputy Director General (TERM) - Jharkhand
Member
- 12 State Head of BSNL
Member
- 13 State Heads of Telecom/Infrastructure Provider concerned
Member
(against whom complaints are received)
- 14 An eminent public person to be nominated by the chairman of STC
Member

Duties & Functions

- (i) STC shall act as the appellate body of DTC.
- (ii) STC shall have powers to amend, cancel, endorse the decisions of DTC or to remand back to DTC for considering afresh.
- (iii) The recommendations of STC/DTC shall be adhered to by Municipal Corporation/ Municipality/Nagar Panchayat/Nagar Parishad/ Panchayat Samiti or any other authority related to the subject.

15. Changes in the Policy

This policy shall be suitably adjusted to accommodate changes that may be necessitated on account of any technology or regulatory changes which may be introduced by the Department of Telecommunications, Government of India or any other competent authority in order to keep this policy dynamically responsible to changing technology, regulatory regime or any other unforeseen development.

By order of the Governor of Jharkhand

Sd/-
(Sunil Kumar Barnwal)
Secretary to the Government

Memo No.:

Ranchi, Dated:-

Copy to:- The Superintendent, Govt. Printing Press, Ranchi for publication in the extra ordinary Gazette for general information. It is requested that one hundred copy of the Gazette may kindly be made available to this Dept.

Sd/-
Secretary to the Government

Memo No.:

Ranchi, Dated:-

Copy to:- Chief Secretary/Development Commissioner/Member Revenue Board/All Additional Chief Secretaries/Principal Secretary to Governor/Principal Secretary to CM/All Principal Secretaries/All Secretaries/All Commissioners/All Deputy Commissioners for information and necessary action.

Sd/-
Secretary to the Government

Memo No.:

Ranchi, Dated:-

Copy to:- Assistant Director, Department of Information Technology & e-Gov for publishing in e-Gazette.

Secretary to the Government

FORM-I**FORM OF APPLICATION FOR INSTALLATION OF GROUND BASED TOWERS (GBT)/ROOF TOP TOWERS (RTT)/ROOF TOP POLES (RTP)**

To :

The Pr Secretary/Secretary IT,
Govt of Jharkhand , Ranchi

Letter No:

Date:

1. **Company Details:**

Name of the Infrastructure Provider/Telecom Service Provider			
Address of Registered Office/Head office			
Address for Local Correspondence	Address		
	Phone No		
	Email ID		
Authorized Person with designation	Name		
	Phone No		
	Email ID		
	Designation		
DOT License Details	License No & date:		
	Validity	From----- To----- -	

2. Communication/Mobile Tower Details (for which permission required)

Location of GBT/RTT/RTP	Type of tower (GBT/RTT/RT P)	Plot No	Khat a No	Ward No	Dist	Latitude	Longitude	Panchayat to be covered with GPRS/Edge with good signal (better than -95 db)*	Panchayat covered by leakage signal upto -103 db *

- In case for Rural BTs only.

3. Owner Details

Location of GBT/RTT/RTP	Name of the House/land Owner	Agreement No	Agreement date	Period of agreement

3. List of documents attached as per para 3 of the Policy

SI No	List of documents

4. Payment Details

Total No of GBT/RTT/RTP Locations	Total amount deposited	Date of deposit	Receipt No

Certified that all the information/documents furnished above are authenticated and true to best of my knowledge.

Signature of the Authorized Authority Designation

FORM II**CERTIFICATE OF PERMISSION/NOC**

DatedPermission No.....

Permission/NOC is granted to Mr/Ms/M/s.....
under Policy.....for mobile
 tower at following locations:

Sl No	Location of GBT/RTT/RTP	Type of tower (GBT/RTT/RTP)	Plot No	Khata No	Ward No	Dist

Seal & Signature of Competent Authority

FORM III

INDEMNITY BOND

I,S/oResident of
on behalf of M/sdeclare
 that I have applied for erecting /constructing mobile tower at land /building of Mr/Ms/M/s
situated at (Address of location) Plot noKhata
 no.....Revenue village/thana.....Dist..... (In case of more than
 one location details may be attached separately).

I, in the event of any civil/criminal case vow that for granting permission to erect
 mobile tower the Govt of Jharkhand shall not be liable in any way and the company
 (M/s.....) shall be fully responsible in the event of any damage caused
 to tower or any individual by natural disaster /other event/accidental damages/ fire/loss
 or breakage.

I also vow that the company (M/s.....) shall be bound to comply
 with the provisions as above conditions as laid down in this Policy.

(to be executed in non – judicial stamp of Rs. 100/- denomination)

Signature Seal
 Applicant/Authorised Representative

Name of the Company/Firm
